

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 30 जुलाई, 2015

विषय- राज्य के एक प्रशासकीय विभाग द्वारा दूसरे प्रशासकीय विभाग को भूमि/भवन के निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-XXVII(7)50(39)-2015/2014 दि०-09.07.2015 तथा शासनादेश सं०-260/वि०अनु०-3/2002 दि०-15.02.2002 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में राजस्व विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध भूमि को एक सेवा विभाग से दूसरे सेवा विभाग को हस्तांतरित करने के अधिकार जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है। अतः जिन योजनाओं पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, और उनका क्रियान्वयन भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है, उन परियोजना/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (विभिन्न प्रशासकीय विभागों के स्वामित्व/प्रबन्धन की भूमि को छोड़कर) हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. दिनांक-09.07.2015 तक के एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव जिन पर उच्चानुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, उनके आदेश यथाशीघ्र निर्गत किये जायेंगे।
2. एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के समस्त प्रस्तावों को जिन पर अभी तक आदेश निर्गत नहीं हुए हैं, अथवा जो विभिन्न स्तरों पर लम्बित है, अथवा जिनका विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जा रहा है, उन प्रस्तावों को जिलाधिकारी को वापस कर दिया जाये क्योंकि शासनादेश दि०-09.07.2015 में जिलाधिकारी स्तर पर ही इन मामलों में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के मामलों, जो जिलाधिकारियों द्वारा दि०-09.07.2015 के उपरान्त सन्दर्भित किये गये हैं, उन सभी मामलों में जिलाधिकारियों द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी।
4. एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण का कोई ऐसा प्रकरण जिस पर शासन तथा जिलाधिकारी दोनों स्तरों से आदेश जारी किया गया हो, के सम्बन्ध में शासन का आदेश मान्य होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

पृ०प०संख्या-1887/समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाइल।

5. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण उत्तराखण्ड सरकार के मा० मंत्री महोदय के संस्तुति प्रेषित।

आज्ञा से,
(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।

01/8